भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1561
गुरुवार, 13 फरवरी, 2025/ 24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तन अवसंरचना का विकास

1561. श्री कुलदीप इंदौराः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तन अवसंरचना के विकास के लिए कोई रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत विमानपत्तनों की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आधुनिक विमानपत्तन सुविधाएं उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 जारी की है, जिसका उद्देश्य ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाओं के साथ-साथ 'उड़ान' योजना के माध्यम से हवाईअड्डों की अवसंरचना का विकास करना और इसके सभी उप-क्षेत्रों अर्थात एयरलाइनों, एमआरओ, एफ़टीओ, आदि के विकास सहित सामंजस्यपूर्ण ढंग से नागर विमानन क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। वर्ष 2014 से 12 गरीन्फ़ील्ड विमानपत्तनों का निर्माण करके प्रचालन आरंभ कर दिए गए हैं।

विमानन अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य पीपीपी हवाईअड्डा प्रचालकों ने हवाई यातायात और यात्रियों की संख्या में वृद्धि की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए देश में विभिन्न हवाईअड्डों के विकास/ उन्नयन/ आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक 91,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय योजना शुरू की है। परियोजनाओं में नए हवाईअड्डे, मौजूदा टर्मिनलों का विस्तार और सुधार, अतिरिक्त यात्री सुविधाएं, नए टर्मिनल, रनवे और एप्रनों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, तथा एएनएस (वायु दिक्चालन सेवाएँ) से संबंधित कार्य जैसे नियंत्रण टावर और तकनीकी ब्लॉक शामिल हैं।

जनसाधारण को किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में। वर्ष 2016 में इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से, 'उड़ान' योजना में 88 असेवित/ अल्पसेवित हवाईअड्डों का प्रचालन शुरू किया है, जिसमें 2 वॉटर एयरोड्रोम और 13 हेलीपोर्ट शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रचालनशील हवाईअड्डों/ हेलीपोर्टों/ वॉटर एयरोड्रोमों की कुल संख्या जो वर्ष 2014 में 74 थी, वर्ष 2024 में बढ़कर 159 हो गई है।

(घ): वर्तमान में, राजस्थान में सात प्रचालनशील हवाईअड्डे हैं, जिनमें जयपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, किशनगढ़, कोटा और उदयपुर में तीन घरेलू हवाईअड्डे और बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में तीन घरेलू सिविल एन्क्लेव शामिल हैं।

(ङ): श्रीगंगानगर के लालगढ़ में अवस्थित मौजूदा हवाईपट्टी को 'उड़ान' योजना दस्तावेज में असेवित हवाईअड्डों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। आरसीएस-उड़ान योजना के तहत, असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/ उन्नयन, वैध बोली के माध्यम से उन्हें चिह्नित करके और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को अवार्ड करके किया जाता है।

हनुमानगढ़ के संबंध में, अब तक, नागर विमानन मंत्रालय को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के तहत हनुमानगढ़ जिले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार या किसी अन्य हवाईअड्डा विकासकर्ता से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****